लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5025

26 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

सस्ता इस्पात आयात

5025. श्री राहुल शेवालेः
श्री कृपाल बालाजी तुमानेः
श्री अरविंद सावंतः
श्री संजय धोत्रेः
श्रीमती भावना गवली (पाटील):
श्री भर्तृहरि महताबः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इस्पात उद्योग सस्ते इस्पात आयात में वृद्धि और इस्पात की घरेलू और वैश्विक मांग में गिरावट के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में कितना स्वदेशी इस्पात उत्पादित और आयात किया गया है;

(ग) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान इस्पात आयात में वृद्धि के विरुद्ध विभिन्न घरेलू इस्पात विनिर्माताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है;

(घ) क्या देश की अग्रणी इस्पात कंपनियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भारी नुकसान हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का इस्पात उद्योग को एक विशेष पैकेज प्रदान करने का विचार है ताकि यह संकट से उभर सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सस्ते इस्पात आयात के विरुद्ध घरेलू इस्पात उद्योग की सुरक्षा और संवर्धन के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) से (ग): भारतीय इस्पात कंपनियाँ विगत में इस्पात के बड़े व्यवसायियों द्वारा इस्पात की डंपिंग किए जाने के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रहे थे। वर्ष 2014-15 में कुल इस्पात (अलॉय + गैर-अलॉय) के आयातों में 75.5% वृद्धि हुई थी। वर्ष 2014-15 के दौरान घरेलू इस्पात की कीमतों में अत्यधिक गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई थी, जो वर्ष 2015-16 तक जारी रही। घरेलू इस्पात निर्माताओं ने उपयुक्त व्यापारिक उपचारी उपाय किए जाने हेतु नामित प्राधिकारी के पास अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं। सरकार ने अनुचित व्यापार को रोकने के लिए अन्य के साथ-साथ तद्नुसार एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी), काउंटर वेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) और सेफगार्ड ड्यूटी (एसडी) जैसे उपाय अधिसूचित किए हैं। सरकार द्वारा किए गए इन उपचारी कार्रवाइयों से अनुचित व्यापार में रोक लगी है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान घरेलू इस्पात उत्पादन और आयात की मात्रा निम्नवत है:

(मात्रा मिलियन टन में)

वित्तीय वर्ष	बिक्री हेतु इस्पात उत्पादन (एमटी)	आयात (एमटी)
2014-15	92.15	9.3
2015-16	90.9	11.7
2016-17	100.7	7.2
2017-18 अप्रैल-जून	88.37	6.45

स्रोत: जेपीसी

(घ): सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माताओं समेत कुछेक प्रमुख इस्पात कंपनियों का वार्षिक वित्तीय निष्पादन निम्नवत है:

कंपनी का नाम	कर-पश्चात लाभ (करोड़ रुपये में)			
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सेल	2616.48	2092.68	-4137.26	-2833.24
आरआईएनएल	366.45	62.38	-1420.64	-1235.62
टाटा स्टील लिमिटेड	6412.19	6439.12	955.65	3,444.55
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	1334.51	2166.48	-3498.28	3576.54
जेएसपीएल	1291.95	-310.68	-1018.88	-986.45
भूषण स्टील लिमिटेड	61.96	-1253.83	-2839.37	-3501.12
स्रोत: ईआरयू				

वर्ष 2015-16 के दौरान इस्पात की अग्रणी कंपनियों ने अन्य के साथ-साथ अनुचित व्यापार और घटती कीमतों के कारण सामान्यतः हानियों का सामना किया है। सरकार द्वारा उपचारी उपाय करने के पश्चात् वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है। वर्ष 2017-18 की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान प्रमुख इस्पात कंपनियों का वित्तीय निष्पादन निम्नवत है:

कंपनी का नाम	कर-पश्चात् लाभ (करोड़ रुपये में)		
	जून, 2017	सितंबर, 2017	दिसंबर, 2017
सेल	-801.38	-538.32	47.48
आरआईएनएल	-430.59	-295.58	-
टाटा स्टील लिमिटेड	377.30	1213.14	1474.20
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	282.00	883.00	1410.00
जेएसपीएल	-177.06	-254.56	-73.07
भूषण स्टील लिमिटेड	-750.07	-467.43	-1606.63
स्रोत: ईआरयू			

(ङ) और (च): सरकार इस्पात उद्योग को कोई विशेष पैकेज देने की योजना नहीं बना रही है। इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। सरकार इस्पात उत्पादों के स्वतंत्र और उचित व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार घरेलू इस्पात निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर उचित प्रक्रिया अपनाकर पहल करते हुए एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी), काउंटर वेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) और सेफगार्ड ड्यूटी (एसडी) जैसे व्यापारिक उपचारी उपायों को अधिसूचित करती है।

*****